*वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव: नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीति विकल्प**

शक्तिकान्त दास

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, जिसके पास वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन/सीसेन) फोरम की अध्यक्षता है, मैं इस 59वें सीसेन गवर्नर सम्मेलन में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और अन्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष के इस समय में मुंबई का मौसम सुहावना है और मुझे आशा है कि आपको दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए कुछ समय मिलेगा। इस सभागृह में हर कोई जानता है कि सदस्य केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और नीति समन्वय को बढ़ावा देने में सीसेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और परिणामस्वरूप क्षेत्रीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, समुत्थानशीलता और टिकाऊ संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

हम यहां एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एकत्र हुए हैं जब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन निकट भविष्य में अनिश्चितताओं के साथ कई चुनौतियां भी हैं। सम्मेलन का विषय "आर्थिक बाधाओं को दूर करना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ" (नेविगेटिंग इकॉनोमिक हेडविंड्स एंड एडवान्सिंग फिनान्शियल इनक्लूशन: पर्सपेक्टिव्ज़ एंड चैलेंजेस) वर्तमान नीतिगत दुविधा स्थिति में उपयुक्त विषय है जिसका आज क्षेत्र के सभी केंद्रीय बैंक सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में विवेकपूर्ण समष्टिगत वित्तीय नीतियां हम सभी के लिए न केवल वर्तमान अस्थिरता से निपटने के लिए, बल्कि अधिक आशाजनक भविष्य की दिशा में एक रास्ता तय करने के लिए और भी अधिक महत्व रखती हैं। यह जानकर खुशी होती है कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं और आने वाले वर्षों में निरंतर प्रगति के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में उच्च स्तर के एकीकरण की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में हुआ गहन विचार-विमर्श हमारी भविष्य की नीति निर्माण के लिए कुछ लाभकारी निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

मैंने आज अपने संबोधन के लिए विषय "वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव: नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीति विकल्प" (फंडामेंटल शिफ्ट्स इन दी ग्लोबल इकोनॉमी : न्यू कॉम्पलेक्सिटीज़, चैलेंजेस एंड पॉलिसी ऑप्शन्स) चुना है। सबसे पहले मैं संकट के पहले के दौर के बिल्कुल विपरीत हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता के बारे में बात करना चाहूँगा। इसके बाद मैं उन उभरते रुझानों और बदलावों को रेखांकित करूंगा जो वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनीय रूप से नया आकार दे रहे हैं और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। अंत में मैं हमारे क्षेत्र की व्यापक आर्थिक रूपरेखा को चित्रित करने का प्रयास करूंगा, जिसके बाद भविष्य के लिए कुछ नीति विकल्पों पर प्रकाश भी डालना चाहूंगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की समुत्थानशीलता

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम अनुमान के अनुसार वैश्विक संवृद्धि 2024 में 3.1 प्रतिशत और 2025 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024 के लिए पूर्वानुमान अक्टूबर 2023 के अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक ऊपर संशोधित किया गया है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था कहीं अधिक समुत्थानशील रही है और बार-बार आने वाले आघातों का बेहतर ढंग से सामना कर रही है। यहां तक कि वित्तीय प्रणाली ने भी मोटे तौर पर दुनिया भर में आयी अभूतपूर्व मौद्रिक सख्ती का सामना किया है। विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की समुत्थानशीलता अस्थिरता के पिछले दौर के विपरीत है, जिसमें ईएमई को नुकसान उठाना पड़ा था। ईएमई ने संभवत: अपने पिछले अनुभव से सीख ली है और इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि इस तथाकथित सॉफ्ट लैंडिंग का अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है लेकिन मैं कुछ संभावित कारकों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

पहली बात यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) और वैश्विक उथल-पुथल के पिछले दौर के दौरान बैंकिंग संकट एक

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 फरवरी 2024 को मुंबई में 59वें सीसेन गवर्नर सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण।

सामान्य बात थी जिसमें अपर्याप्त पूंजी वाले बैंक संकट के मूल में थे। इसके विपरीत, इस बार ईएमई को मार्च 2023 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में हुई हालिया बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल से प्रतिकूल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। यह बेसल III मानदंडों को व्यापक रूप से अपनाने और पर्यवेक्षी प्रथाओं में सुधारों के माध्यम से विवेकपूर्ण विनियमन को मजबूत करने के कारण संभव हुआ है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। दूसरा, हाल के वर्षों में ईएमई की बेहतर समष्टि आर्थिक मौलिक स्थिति और बफर ने पिछले चार वर्षों के वैश्विक आघातों के खिलाफ राहत प्रदान की है। तीसरा, कोविड-19 के दौरान उपलब्ध कराए गए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन को पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया है, खासकर एई में। इससे एई द्वारा नीति को सख़्त करने से होने वाले प्रसार प्रभाव की मात्रा अब तक कुछ हद तक सीमित रही है। चौथा, महामारी के बाद उद्योग और सेवाओं में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार में तेजी आई है। इससे कई ईएमई में उत्पादकता बढ़ी है और मौद्रिक सख्ती जैसे कारकों से उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई हुई है। वास्तव में देखें तो प्रौद्योगिकी ने ईएमई के लिए, विशेषकर सेवा क्षेत्र में, अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। पांचवां, केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए सुविचारित और स्पष्ट संचार को भी उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रभावी संचार भावी मार्गदर्शन प्रदान करने और बाजार की अपेक्षाओं को नियंत्रित रखने में पहले की तुलना में और भी मजबूत साधन बन गया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का बदलता परिदृश्य

महामारी जीवन और आजीविका के नुकसान के मामले में एक अभूतपूर्व संकट थी। हाल के मानव इतिहास में कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव, तेल की कीमतों में तेज उछाल और वित्तीय उथल-पुथल मंदी के कारण रहे हैं। वैश्विक वित्तीय संकट भी बढ़ते वित्तीय उतार-चढ़ाव को नीति निर्माताओं द्वारा अनदेखा किए जाने का परिणाम था। इसके विपरीत, महामारी एक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल था जिसके कारण एक अज्ञात प्रतिकूल स्थिति में जीवन बचाने के लिए आर्थिक गतिविधि और गतिशीलता पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके अलावा नीति निर्माताओं के लिए कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट या तैयार साधन नहीं था। इस वजह से उन्हें अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर महामारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपना कार्य जारी रखते हुए उचित नीति प्रतिक्रियाएँ तैयार करने में कुछ नया करना और सीखना पड़ा।

महामारी का प्रभाव कम हो ही रहा था कि तभी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों ने नई चुनौतियों को जन्म दिया और मुद्रास्फीति स्थिति जोरदार तरीके से फिर उत्पन्न हुई। मौद्रिक नीति में परिणामी व्यवस्था परिवर्तन ने वित्तीय बाजार की भावनाओं को प्रभावित किया जिससे 'भारी अस्थिरता' का दौर शुरू हो गया। मौजूदा मॉडल, जो आंकड़ों के ऐतिहासिक पैटर्न को समझाने के लिए बनाए गए थे, नई वास्तविकताओं को समझाने में असफल पाए गए। इन मॉडलों को वर्तमान में हो रहे आघातों, भू-आर्थिक तनाव और आपूर्ति शृंखला में बदलाव आने से चुनौती मिल रही है। उदाहरण के लिए, समग्र विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल यह समझाने में असफल रहे कि हम महामारी के बाद किन बातों को जान पाए। प्रारंभ में सेवाओं से वस्तुओं की ओर और फिर वस्तुओं से सेवाओं की ओर मांग में चक्रण होता रहा। महामारी के कारण विलंबित और भावनाओं के अचानक उमड़ आने से खर्च करने का दौर आया। इन क्षेत्रीय असंतुलनों ने मुद्रास्फीति के स्तर को ऊँचा बनाए रखा। महामारी ने वास्तव में अधिक विस्तृत और क्षेत्रीय विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। एक तरह से आर्थिक सोच में आमूल-चूल बदलाव आ रहे हैं। इनमें से कुछ मुद्दों पर विस्तार से बात करना चाहूंगा।

सबसे पहले, महामारी के बाद की दुनिया श्रम बाजार की गतिशीलता, कार्य प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकीय गहनता में बदलाव के मामले में मौलिक रूप से बदल गई है। घर से काम, ऑनलाइन शिक्षा और खरीदारी को व्यापक स्वीकृति मिली है, जिससे हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके में बदलाव आया है। प्रौद्योगिकीय नवाचार और डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्याप्त हो रहा है। व्यवसाय अपने अस्तित्व के लिए इन प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ नए अवसर खोलती हैं लेकिन वे चुनौतियाँ भी पेश करती हैं जिनका हमें समाधान करने की आवश्यकता है।

दूसरा, महामारी से पहले मौद्रिक नीति अपस्फीतिकारी दबावों का सामना करते हुए संवृद्धि को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयास में लंबे समय तक निम्न स्तर पर चल रही थी। यूक्रेन युद्ध के बाद मुद्रास्फीतिक दबावों का सामना करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा "लंबे समय तक उच्च" दरों का रुख अपनाने से यह स्थिति अचानक और तेजी से बदल गई। उच्च ब्याज दरों और अल्प संवृद्धि के माहौल में ऋण की अधिकता की स्थिति में इस तरह के नीतिगत परिवर्तन से कई देशों में समष्टि आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। ऊंची ब्याज दरें न केवल भारी कर्ज वाले देशों पर ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ाती हैं बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र पर भी असर डालती हैं, जैसा कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल के दौरान देखा गया था। एक चरम अर्थ में मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के बीच अत्युच्च संतुलन के कारण देशों की उच्च ऋणग्रस्तता मौद्रिक नीति के लिए चुनौती बन सकती है।

तीसरा, वैश्वीकरण ने उत्पादकता बढ़ाकर, वैश्विक मूल्य शृंखलाएं बनाकर और देशों में पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। लेकिन वैश्वीकरण के लाभ सभी देशों में समान रूप से नहीं पहुँचे हैं। भू-आर्थिक विखंडन के हालिया रुझानों को देखते हुए दुनिया भर में औद्योगिक और व्यापार नीतियों में बदलाव आ रहा है। कई अर्थव्यवस्थाएं अब सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को री-शोरिंग, नियर-शोरिंग तथा फ्रेंड-शोरिंग[1] रही हैं। नतीजतन व्यापार विखंडन, प्रौद्योगिकीय विघटन, बाधित पूंजी प्रवाह और श्रम श्रेत्र में परिवर्तन बढ़ रहे हैं। ये सभी वस्तु और सेवाओं के की दृष्टि से एक एकीकृत वैश्विक बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं देते हैं।

चौथा, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के नजरिए से बार-बार होने वाले भू-राजनीतिक टकराव और प्रमुख व्यापार मार्गों में रुकावटों के कारण खाद्य, ऊर्जा और महत्वपूर्ण औद्योगिक सामानों के व्यापार प्रवाह में आने वाले व्यवधान खाद्य सुरक्षा और समष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय बाजारों और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता को देखते हुए ये देश बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे माहौल में, महत्वपूर्ण वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार की एक मजबूत व्यवस्था के रूप में घरेलू बफर का निर्माण ईएमई के लिए अनिवार्य हो जाता है।

पांचवां, केंद्रीय बैंकों द्वारा अब तक प्रयोग किए जाने वाले समष्टि आर्थिक मॉडल मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष पर केंद्रित हैं। आपूर्ति पक्ष के कारकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। महामारी, उसके बाद युद्ध और परिणामी आपूर्ति शृंखला व्यवधानों ने आपूर्ति पक्ष पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। एक के बाद एक आने वाले आपूर्ति आघात, जैसा कि हमने हाल ही में देखा, लगातार मुद्रास्फीति दबाव का कारण बना, तब भी जब कुल मांग अनुचित रूप से अधिक नहीं थी। इस संदर्भ में, मुद्रास्फीति पर आपूर्ति-पक्ष या लागत-प्रेरित दबाव (कॉस्ट-पुश प्रेशर) के प्रबंधन में सरकारों की भूमिका को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। आगे की बात करें तो मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष की बेहतर समझ बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

इस पृष्ठभूमि में अब मैं हमारे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक स्थितियों पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा।

सीसेन (एसईएसीईएन) क्षेत्र का समष्टि आर्थिक अवलोकन

दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने बड़े वैश्विक आघातों से निपटने में उल्लेखनीय समुत्थानशीलता दिखाई है। काफी हद तक इसका श्रेय बेहतर मौद्रिक और व्यापक आर्थिक नीति ढांचे को दिया जा सकता है जिसे इन देशों ने हाल के वर्षों में अपनाया है। इस क्षेत्र में संवृद्धि मजबूत बनी हुई है जबकि मुद्रास्फीति ओईसीडी औसत से कम रही है। क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि को खुदरा व्यापार, डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में समुत्थानशील सेवा गतिविधि का सहारा मिला है। यह क्षेत्र घनिष्ठ व्यापार और श्रम प्रवाह संबंधों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण का एक मॉडल बना हुआ है। फिर भी, अधिक व्यापार एकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। मैं दृढ़ता से

[1] शब्द "रीशोरिंग" का तात्पर्य किसी देश द्वारा वैश्विक आपूर्ति शृंखला के (उसके भाग) को घर वापस स्थानांतरित करने (या "नियरशोरिंग" के मामले में भौगोलिक दृष्टि से घर के करीब) से है। "फ्रेंड-शोरिंग" घरेलू देश से संबद्ध देशों और एकसमान रणनीतिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं वाले विश्वसनीय भागीदारों तक आपूर्ति-शृंखला नेटवर्क और इनपुट स्रोत को सीमित करता है।

महसूस करता हूं कि सीसेन देशों के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं और मजबूत हो सकती हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और वह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विवेकपूर्ण मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों ने इन कठिन परिस्थितियों से निपटने में भारत की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि 2024-25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो लगातार चौथे वर्ष 7 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि को चिह्नित करेगा। मुद्रास्फीति 2022 के ग्रीष्मकाल के उच्चतम स्तर से कम हो गई है। तथापि बार-बार होने वाले खाद्य कीमतों के आघात और भू-राजनीतिक मोर्चे पर नए सिरे से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता मुद्रास्फीति कम करने की प्रक्रिया के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। हम अवस्फीति के अंतिम चरण से गुजरने के लिए सतर्क हैं क्योंकि यात्रा का यह हिस्सा अक्सर सबसे कठिन होता है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि स्थिर और निम्न मुद्रास्फीति टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक आधार प्रदान करेगी।

प्रतिकूल आघातों की किसी शृंखला का सामना करने के लिए भारत द्वारा की गई समन्वित नीतिगत कार्रवाई भविष्य के लिए एक अच्छा खाका हो सकती है। जबकि मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने और मांग-प्रेरित दबाव को कम करने पर काम किया, उधर सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप ने आपूर्ति-पक्ष के दबाव को कम किया और लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया। प्रभावी राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय भारत की सफलता के मूल में था।

अब मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की भविष्य की दिशा के लिए कुछ संभावित नीतिगत विकल्पों की ओर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में नई वास्तविकताएं आकार लेंगी।

भविष्य के नीतिगत विकल्प

सबसे पहले हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। इस संबंध में, "महत्वपूर्ण खनिज गलियारे" और सुरक्षित खाद्य सुरक्षा के लिए "खाद्य गलियारे" पर समझौते आवश्यक हैं। ऐसी व्यवस्थाएँ निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए।

दूसरा, जलवायु परिवर्तन जैसे सामान्य हित और तत्काल जरूरतों वाले क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है, जहां कोई भी देश अपने दम पर रणनीति तैयार नहीं कर सकता है। आर्थिक गतिविधि में व्यवधान और संवृद्धि क्षमता के नुकसान से बचने के लिए सुचारु और सुव्यवस्थित हरित परिवर्तन आवश्यक है। सुचारु हरित परिवर्तन के लिए निवेश की आवश्यकताएं बड़ी हैं, जबकि हरित परियोजनाओं के लिए वास्तविक वित्तीय प्रवाह अत्यधिक विषम है और वह बड़े पैमाने पर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। परिणामस्वरूप ईएमई में हरित पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें वित्तीय स्थिरता पर हरित परिवर्तन के संभावित प्रभावों के प्रति भी सचेत रहना होगा।

तीसरा, बुनियादी ढांचे में सुधार दीर्घकालिक संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि दृश्य बुनियादी ढांचे (हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर) (सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, पानी) में निवेश महत्वपूर्ण है, वहीं अदृश्य बुनियादी ढांचा (सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) (शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी, वित्तीय, संस्थागत) बनाने पर भी उतना ही जोर देना होगा। कौशल उन्नयन और महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना प्रभावी श्रम आपूर्ति और इस क्षेत्र की संभावित संवृद्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

चौथा, भारत का यह अनुभव रहा है कि लागत में कटौती करते हुए वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का उपयोग किया जा सकता है। इंडिया स्टैक और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में हमारे निरंतर जुड़ाव ने, विशेष रूप से महामारी के दौरान और उसके बाद, हमें यह विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे बढ़ने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक सार्वजनिक हित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। भारतीय यूपीआई के साथ कुछ अन्य देशों की तेज़ भुगतान प्रणालियों का जुड़ाव यूपीआई को सीमापार भुगतान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता प्रदान करता है।

पांचवां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसे नए प्रौद्योगिकीय विकास व्यवसायों की कार्यकुशलता और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। तथापि, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय बाजार के विनियामकों को वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने में एआई और एमएल के संभावित दुरुपयोग के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है।

संक्षेप में

वैश्विक अर्थव्यवस्था चौराहे पर खड़ी है। चुनौतियाँ तो भरपूर हैं, लेकिन नये अवसर भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हम सब मिलकर यहां से जो मार्ग अपनाएंगे वही आने वाले समय में हमारा भाग्य तय करेगा। हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई वास्तविकताओं के अनुरूप हों। इस अनिश्चित विश्व में केंद्रीय बैंकों को मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सक्रिय होने की आवश्यकता है।

इस माहौल में सहयोग एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए हमें बेहतर ढंग से संकल्प करने और समन्वय की आवश्यकता है। सीसेन, जो इस भू-क्षेत्र के केंद्रीय बैंकों के लिए एक मंच के रूप में है, उन्नत प्रगति और समृद्धि के लिए कई क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करता है। देशों के बीच सहयोग में तुलनात्मक लाभ और संसाधन साझाकरण के सिद्धांतों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हममें से प्रत्येक को लाभ हो। आइए हम अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्थाओं की भलाई हासिल करने के लिए अपने विचार-विमर्श को और ऊंचे स्तर पर ले जाएं।

धन्यवाद, नमस्कार.